देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित | www.page3news.in | नगर संस्करण वर्ष 16 अंक: 199 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...साख बचाने की है चुनौती

पेज श्री

देहरादून, बृहस्पतिवार, 11 नवंबर 2021

मौसम अधिकतम 27.0° न्यूनतम 24.0°

39239.40

2 परमाणु रिएक्टर शुरू करेगा फ्रांस

7 आईसीसी रैंकिंग में बाबर आजम नंबर वन

तालिबान के खिलाफ प्लान तैयार

भारत के नेतृत्व में अफगानिस्तान पर 7 देशों की बैठक

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल की अध्यक्षता में अफगानिस्तान पर दिल्ली में अहम बैठक हुई। वार्ता में इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का उपयोग किसी भी आतंकवादी कृत्य के लिए नहीं होने दिया जाएगा। भारत के आमंत्रण पर रूस, अमेरिका, उजबेकिस्तान और ताजिकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार क्षेत्रीय सुरक्षा डायलाग में हिस्सा ले रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर पैदा हुई चनौतियों से लड़ने और अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाने के उपायों पर चर्चा की जा रही है। इस बैठक के लिए चीन और पाकिस्तान को भी न्योता दिया गया था, लेकिन इन दोनों देशों ने बैठक में शामिल होने से इन्कार कर दिया। अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद नामक इस बैठक की मेजबानी भारत के एनएसए अजीत डोभाल कर रहे हैं। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारे विचार–विमर्श प्रोडक्टिव व उपयोगी होंगे और अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने और हमारी सामूहिक सुरक्षा बढ़ाने में योगदान देंगे। हम सब अफगानिस्तान में हो रही घटनाओं को गौर से देख रहे हैं। इसके लोगों के लिए ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और क्षेत्र के लिए भी इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और ईरान सहित पांचों मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से मुलाकात की।

अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में कजाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष करीम मासीमोव ने कहा कि हम अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित हैं। अफगानों की सामाजिक अंत आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और देश मानवीय संकट का सामना कर रहा है। हमें मानवीय सहायता बढ़ाने की जरूरत है। ताजिकिस्तान की सुरक्षा परिषद के सचिव नसरलो रहमतजोन महमूदजोदा ने कहा कि हम पड़ोसी देश के रूप में अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने वाले सभी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तैयार हैं। चूंकि अफगानिस्तान के साथ हमारी लंबी सीमा है, वर्तमान स्थिति मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद के लिए अतिरिक्त जोखिम और संभावनाएं पैदा करती है।

रूस ने निभाया भारत का साथ

अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद रूस निश्चित तौर पर इसे अमेरिका की हार के तौर पर देख रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से यह लगातार दिखाया जा रहा है कि रूस उसकी अफगान नीति के साथ है, जबकि हकीकत यह है कि अफगानिस्तान को लेकर भारत और रूस लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं। रूस के लिए दिल्ली डायलाग काफी अहम है।

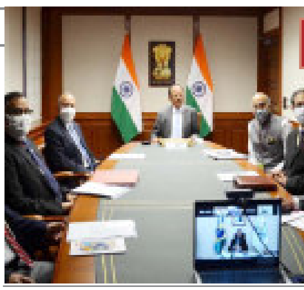

पाकिस्तान और चीन की रहेगी नजर

पाकिस्तान और चीन की सीमाएं भी सीधे तौर पर अफगानिस्तान से जुड़ी हैं। पाकिस्तान खुद को अफगानिस्तान के मामले में काफी प्रभावी भूमिका में मानता है। हालांकि अफगानिस्तान के तमाम गुट एक मत नहीं हैं और किसी एक व्यवस्था के प्रभाव में भी नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान और चीन दोनों की नजर नई दिल्ली में होने वाले डेवलपमेंट पर टिके रहने के आसार हैं। इसका एक बड़ा कारण ईरान और रूस के एनएसए की सम्मेलन में मौजूदगी है।

भारत को क्या फायदा होगा?

यह सबसे बड़ा सवाल है। भारत के डिप्टी एनएसए पंकज सरन भी कहते हैं कि यह नहीं बताया जा सकता कि अफगानिस्तान में आगे क्या होगा? इसमें कोई दो राय नहीं कि अफगानिस्तान की स्थिति बेहद जटिल है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत के आपसी तालमेल बढ़ाने की पहल से अफगानिस्तान में चल रहे घटनाक्रमों, सूचनाओं की सीधी और सटीक जानकारी मिल सकेगी। आतंकवाद जैसी स्थितियों को रोकने में सहायता तथा वैश्विक स्तर पर पहल के लिए नए साथी मिल सकेंगे। अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा, वहां के लोगों के मानवीय अधिकार, मानवीय सहायता पर जोर देने का जरिया मिल सकेगा। ऐसा करके भारत अफगानिस्तान और उसके माध्यम से अपने हितों की रक्षा का रोड–मैप बना सकेगा।

संक्षिप्त समाचार

सोनीपत में नेशनल रेसलर निशा दहिया की हत्या

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत में नेशनल लेवल की रेसलर निशा दहिया और उसके भाई व मां को हमलावरों ने गोली मार दी। जिसमें निशा दहिया और उसके भाई की मौत हो गई। वहीं, गंभीर हालत में मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावरों ने इस सनसनीखेज घटना को सोनीपत के हलालपुर गांव में अंजाम दिया। हमलावरों पहलवान सुशील कुमार एकेडमी के पास तीनों को गोली मारी।

भारत में कोरोना संक्रमण के सबसे कम मामले

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। भारत में 264 दिनों बाद कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे कम मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में देशभर में 11 हजार 466 केस सामने आए हैं और इस दौरान 460 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि, केरल अब भी पेरशानी का सबब बना हुआ है।

महापर्व छठ पर आस्था का उल्लास

नई दिल्ली। देश में गंगा एवं अन्य नदियों के किनारे बुधवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को श्रद्धालुओं ने छठ का पहला अर्घ्य दिया। पटना में मनेर, दानापुर से लेकर बाढ़, फतुहा और मोकामा तक गंगा घाटों पर प्रशासन के साथ ही स्थानीय पूजा समितियों की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे। बक्सर के गंगा घाटों पर व्रतियों का पहुंचना दोपहर एक बजे से ही शुरू हो गया था। ऐसा ही नजारा भागलपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, भोजपुर, सारण, वैशाली आदि जिलों में भी देखने को मिला। शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूजा पर घाटों का निरीक्षण करने निकले। अब व्रती गुरुवार की सुबह उगते सूर्य अर्घ्य प्रदान करेंगे।

ढलते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं का जत्था बुधवार दोपहर से ही गंगा घाटों पर पहुंचने लगा। गीत गाते व्रती अलग–अलग शहरों में बने घाटों तक पहुंचे। कई लोगों ने घरों की छतों पर अस्थाई तालाब बनाकर अर्घ्य दिया।

सांसद विकास निधि फिर से हुई बहाल

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सांसद विकास निधि को बहाल करने की मंजूरी दे दी। कोविड–19 महामारी के मद्देनजर योजना को पिछले साल निलंबित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021–22 की शेष अवधि के लिए योजना को बहाल कर दिया गया है। यह योजना 2025–26 तक जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल में मिलाने के लिए गन्ने से बनने वाले एथेनॉल की कीमतों में 1.47 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों पर केंद्रीय समिति ने दिसंबर 2021 से शुरू हो रहे आपूर्ति वर्ष के लिए एथेनॉल की कीमतों को बढ़ाने का निर्णय लिया है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा एथेनॉल की खरीद के लिए तंत्र को अनुमति दे दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने शर्करा सत्र 2020–21 के लिए अलग–अलग कच्चे माल से बनने वाले एथेनॉल की कीमतों को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

मंजूरी

■कोरोना के कारण दो सालों से था निलंबित

जूट के थैलों में होगी अब खाद्यान्न की पैकिंग

केंद्रीय कैबिनेट ने जूट पैकेजिंग मैटेरियल अधिनियम, 1987 के तहत जूट वर्ष 2021–22 के लिए जूट पैकेजिंग सामग्रियों के लिए आरक्षण मानकों को अनुमति भी प्रदान कर दी। केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने बताया कि यह अनुमति मिलने के बाद 100 फीसदी अनाज और 20 फीसदी चीनी की पैकिंग जूट के थैलों में ही की जाएगी।

Are you Planning to make a Website or already have ?

If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.

Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. I Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

क्लाइमेंट चेंज: कोई भी देश मानकों पर खरा नहीं उतरा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। ब्रिटेन के ग्लासगो में 26वां यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस चल रहा है। इस वजह से दुनियाभर में ग्लोबल वॉर्मिंग, क्लाइमेट चेंज, कार्बन उत्सर्जन, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण जैसे शब्द सुर्खियों में हैं। दुनियाभर के देश धरती को बचाने की कसम खा रहे हैं। नेट–जीरो एमिशन के लिए टारगेट तय कर रहे हैं। लेकिन मंगलवार को जारी हुई क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पर्यावरण सुरक्षा को लेकर दुनियाभर के देश कितने गंभीर हैं, इसकी कलई खोल रही है। टॉप–3 पायदान ही खाली हैं।

ग्लासगो में जारी की गई क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग

ग्लासगो में चल रहे COP–26 से इतर जर्मन वॉच की तरफ से क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी देश ने पर्यावरण सुरक्षा के मोर्चे पर मानकों के हिसाब से पर्याप्त काम नहीं किया। एक बार फिर रैंकिंग में शीर्ष–3 पायदान खाली पड़े रहे। पर्यावरण सुरक्षा के लिए दुनिया में मिसाल माने जाने वाले नॉर्डिक देश (स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे) भी मानकों पर खरे नहीं उतर सके।